क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 298, बुधवार, 28 नवम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी और वह अन्य राज्यों के अपने समकक्षों को ऐसा करने के लिए पत्र भी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ''अखिल शिक्षक, कर्मचारी कल्याण संघ' द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे केजरीवाल ने कहा कि इसको फिर केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मैं इसे लागू कराने के लिए केंद्र से लडूंगा। उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अपने समकक्षों से इस संबंध में बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में देश की सरकार बदलने की ताकत है। मैं केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर कर्मचारियों की मांग तीन महीने में पूरी नहीं की गई, तो वर्ष 2019 में कयामत आएगी। रैली के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री का ''देश का नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो' नारे से स्वागत किया गया।

एनयू छात्र संघ अध्यक्ष को जातिसूचक शब्द से अपमानित किया

छात्र संघ अध्यक्ष ने कुलपति से की शिकायत, कड़ी कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। जवाहलाल नेहरू विविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ अध्यक्ष को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला प्रकाश में आया है। जेएनयू में शिक्षकों की हड़ताल के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष एन साई बालाजी को यहां के जीएसफोर ग्रुप से जेएनयू के सिक्योरिटी इंचार्ज ने जातिसूचक शब्द कहे और उन्हें डरपोक कहा। इस मामले में छात्र संघ अध्यक्ष ने कुलपति से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जेएनयू कुलपति प्रो. जगदीश कुमार को की गई शिकायत में छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा है कि सोमवार को प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से मिलने जा रहे थे, तो उसी समय सुरक्षा प्रभारी ने उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। सुरक्षा प्रभारी द्वारा इस तरह के जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है, क्योंकि यहां देशभर से विद्यार्थी आते हैं। इससे साफ होता है कि जीएसफोर से जुड़े सुरक्षाकर्मी कितने संवेदनहीन है। यह जीएसफोर व जेएनयू दोनों की तरफ से कमी है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीएसफोर अपने कर्मचारियों को जागरूक नहीं करता। छात्र संघ ने कुलपति से इस संबंध में कठोर कार्रवाई की मांग की है।

कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपियों को किया बरी, नहीं मिला कोई सबूत

मुजफ्फरनगर, एजेंसी। उत्तर प्रदेश की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के छह आरोपियों को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया। इन पर 32 साल की एक महिला के साथ बलात्कार करने, घटना का वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर डालने का आरोप था। न्यायाधीश बलराज सिंह ने सोमवार को अपने आदेश में इरशाद, नजर, साजिद, सलाउद्दीन, नौशाद और सत्तार को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

लेबनान के बाइब्लोस शहर में रविवार को आयोजित हनिबाल रेस में हिस्सा लेते प्रतिस्पर्धी। करीब 800 लोगों ने इस बाधा दौड़ में हिस्सा लिया।

उचित मार्गदर्शन से आसान हो जाती है मंजिल

नई दिल्ली, एजेंसी। एक छात्र के लिए जीवन में कामयाबी हासिल करना तब और आसान हो जाता है, जब उसे उचित मार्गदर्शन मिले और इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलता अर्जित करने वाले विद्यालयों के पुरातन छात्र अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें अपने व्यस्ततम कामकाजी जीवन में से कुछ समय निकालकर अपने विद्यालयों में जाना चाहिए और छात्रों को करियर संबंधी जानकारी के साथ ही नैतिकता, सामाजिकता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों से अवगत करना चाहिए।यह बात हरियाणा सेकेंडरी एजुकेशन के महानिदेशक (आईएएस) राकेश गुप्ता ने कही। मौका था पश्चिमी दिल्ली के एल ब्लॉक हरिनगर स्थित एमसीएल सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन ''सुनहरी यादें' के आयोजन का।

सम्मेलन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए विद्या भारती के राष्ट्र महामंत्री हेमचंद जी ने राष्ट्र के प्रति समाज खासकर विद्यार्थियों के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डाला। इससे पहले समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से हुई। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति गीतों का जो दौर चला उसने तमाम श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। लक्की ड्रा के साथ ही मनोरंजन से भरपूर इस समारोह में स्कूल पुरातन छात्र संघ के क्रियाकलापों को दर्शाती एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रधानाचार्य कुलदीप चौहान और पुरातन छात्र संघ के अध्यक्ष अनुभव अग्रवाल ने अतिथियों का धन्यवाद किया।

शिकायतों की अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं

बोर्ड ने अदालत से कहा, एक से 22 नवंबर के दौरान उसे सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट पर वायु प्रदूषण के बारे में 749 शिकायतें मिलीं और इनमें से करीब 500 शिकायतों पर कार्रवाई की गई

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंतग्र बोर्ड से कहा है कि उसकी अधिकृत सोशल मीडिया साइट पर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में मिली करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस मदन लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जरूरत है। अदालत ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से कहा कि आपने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इन लोगों को यह पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंतग्र बोर्ड की ओर से नाडकर्णी ने कहा कि एक से 22 नवंबर के दौरान उसे सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट पर वायु प्रदूषण के बारे में 749 शिकायतें मिलीं और इनमें से करीब 500 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के अदालत के सुझाव पर उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंतग्र बोर्ड इस पर गौर करेगा।

बोर्ड ने एक नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने ट्विटर और फेसबुक पर अपने एकाउन्ट बनाए हैं ताकि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बारे में नागरिक शिकायत दर्ज कर सकें।

खुशखबरी : कार्गो टर्मिनल पर लगी मुहर, दिसंबर से काम होगा शुरू

कानपुर, एजेंसी। गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट अहिरवां से तीन शहरों को शुरू हुई हवाई सेवा सफल रहने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भेजे गए प्रस्ताव को सोमवार को हरीझंडी दे दी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से कानपुर में कार्गो का टर्मिनल (रनवे) छोटा होगा। इसकी वजह यह है कि मौजूदा टर्मिनल में कम जगह है। कार्गो टर्मिनल बनाने की समयसीमा मार्च-2019 तय कर दी गई है। दिसंबर से कार्गो टर्मिनल बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा।

मुंबई, कोलकाता को पहले चरण में चालू होगी कार्गो सेवा

एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों ने बताया कि अभी कानपुर से मुंबई, कोलकाता की कार्गो सेवा चलाने की योजना है। बाद में डिमांड के मुताबिक इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए कार्गो सेवा की निजी कंपनियां कानपुर आकर लोड का आकलन भी करेंगी।

बेंगलुरू फ्लाइट अब नए साल में

स्पाइस जेट की कानपुर से सीधी बेंगलुरू की प्रस्तावित फ्लाइट अब जनवरी-2019 में शुरू करने की तैयारी है इसकी वजह यह है कि बेंगलुरू हवाई अड्डे पर तय शेड्यूल फिट नहीं हो पा रहा है।

भरपूर लोड, अधिकतर सीटें फुल

कानपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की चल रही फ्लाइटों में सोमवार को भरपूर लोड रहा। कानपुर से मुंबई फ्लाइट से 186 यात्री गए तो 181 यात्री आए। इसी तरह 78 सीटर दिल्ली फ्लाइट से 69 यात्री आए तो 71 गए। इसी तरह कानपुर से कोलकाता फ्लाइट से 165 गए तो 151 यात्री आए। सुबह दृष्यता कम होने के बावजूद फ्लाइटें समय से आकर समय पर गईं।

अदालतों में टलते मामलों पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता और कहा

अदालतों में टलते मामलों पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता और कहा

नई दिल्ली, एजेंसी। संविधान दिवस समारोह में देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि संविधान ने हमें कठिन परिस्थितियों में दिशा दिखाई है। सभी के हित में है कि हम संविधान की मूल भावना का आदर करें। यदि हम संवैधानिक मूल्यों का आदर नहीं करेंगे और घमंड और हेकड़ी में रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब चारों ओर अराजकता का माहौल होगा। भारत के चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान के सुझावों पर ध्यान देना हमारे हित में है और ऐसा नहीं करने से अराजकता तेजी से बढ़ेगी। हमारा संविधान हाशिए पर पड़े लोगों के साथ ही बहुमत के विवेक की आवाज है। इसका विवेक अनिश्चितता तथा संकट के वक्त में हमारा मार्गदर्शन करता है। संविधान दिवस केवल उत्सव का दिन ही नहीं है, बल्कि उसके संकल्पों की परीक्षा का भी दिन है।

समय के साथ यह धूमिल नहीं, बल्कि शक्तिशाली हुआ है। 1947 के बाद से हम कहां तक पहुंचे हैं। हमें सोचना होगा कि भारतीय नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिममयी जीवन का लाभ मिला है। निसंदेह देश ने काफी प्रगति की है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। संविधान के अमल पर आने पर इसकी बहुत आलोचना की गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसदीय कामकाज में बार-बार पड़ने वाले व्यवधान और अदालतों में मिलने वाली बार-बार की तारीखों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अदालतों में सुनवाई स्थगित होने से वादकारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। न्यायपालिका ने जल्द न्याय के लिए पहल की है। राष्ट्रपति संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। कोविंद ने कहा कि संविधान ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है। इन तीनों को संविधान को कायम रखने की जिम्मेदारियां दी हैं ताकि वे इसकी (संविधान की) आशाओं एवं उम्मीदों को साकार कर सकें। उन्होंने कहा कि संविधान का संरक्षण करना और उसे मजबूत करना भारत के लोगों की साझेदारी के साथ इन तीनों संस्थाओं का साझा कर्तव्य है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दरअसल, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। राष्ट्रपति ने संसद की कार्यवाही में बार बार पड़ने वाले व्यवधान को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने अदालतों में मामलों की सुनवाई बार - बार स्थगित होने के चलते वादियों को होने वाली परेशानी को लेकर भी चिंता जताई, हालांकि न्यायपालिका इसका सर्वश्रेष्ठ हल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान को अंगीकार करना भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि संविधान में शायद सबसे ज्यादा गतिशील शब्द ''न्याय' है। उन्होंने कहा, ''न्याय एक एकल शब्द है। न्याय एक जटिल और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देने वाला शब्द है। न्याय हमारे संविधान और राष्ट्र निर्माण का साधन तथा लक्ष्य दोनों ही हैं।' राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय को अवश्य ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए समाज का उद्भव और इसकी बदलती मान्यताएं, जीवनशैली और प्रौद्योगिकी और हर कोई इसे संरक्षित रखता है। कोविंद ने कहा कि संविधान स्वतंत्र भारत का आधुनिक ग्रंथ है। संविधान नागरिकों को सशक्त करता है, वहीं नागरिक भी संविधान का पालन कर उसे मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक न्याय सभी वयस्कों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी प्रदान करता है। यह कानून के निर्माण और उनके उचित क्रियान्वयन में भी उन्हें भागीदार बनाता है।

कुंभ 2019: दिसंबर में आएंगी कुंभ के लिए 40 और भगवा बसें

इलाहाबाद, एजेंसी। कुम्भ के लिए 40 और भगवा बसें अगले माह प्रयागराज आने वाली हैं। इन बसों का इस्तेमाल मेले दौरान शटल सेवा के तौर पर किया जाएगा। कुम्भ के लिए एक हजार शटल बसें भेजने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। कुम्भ की ब्रांडिंग के लिए शासन ने हाल ही में 10 भगवा बसें प्रयागराज रोडवेज परिक्षेत्र को भेजी थीं। इन बसों को पांच शहरों के लिए चलाया जा रहा है। दिसंबर में 40 और भगवा बसें शहर में आने वाली हैं। इन बसों को शटल सेवा के रूप में चलाने की तैयारी हो रही है। रोडवेज के रीजनल मैनेजर डॉ. हरिश्चंद्र के अनुसार अगले माह मिलने जा रही 40 और भगवा बसों को कुम्भ तक शटल सेवा के रूप में शहर में चलाया जाएगा। कुम्भ के बाद इन बसों को दूसरे शहरों के लिए चलाया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार (परिवहन) स्वतंत्र देव सिंह ने कुछ माह पहले शहर आगमन पर कुम्भ के लिए एक हजार शटल बसें उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। शटल सेवा के तहत बसें छिवकी, नैनी, झूंसी, फाफामऊ, सूबेदारगंज आदि स्टेशनों से तीर्थयात्रियों को संगम तक पहुंचाने के लिए चलाई जाएंगी। शहर के दूसरे हिस्सों से अन्य हिस्सों को जोड़ने के लिए भी शटल बसें चलाई जाएंगी।

>>> काम काज के लिए हो ऐसी व्यवस्था, सदन में कहा मुख्यमंत्री ने

'दिल्ली पुलिस हो दिल्ली सरकार के पास''

नई दिल्ली, एजेंसी। विधानसभा में सोमवार को एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते तो वे इस्तीफा दे दें। केजरीवाल ने कहा कि उन पर पिछले तीन साल में चार बार हमले हुए हैं, इनके पास केजरीवाल को मरवा देने के सिवा और कोई चारा नहीं है।

केन्द्र सरकार उन्हें सुरक्षा देने में असफल है। विधान सभा ने गृहमंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस होने के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास कर दिया। सत्येन्द्र जैन के प्रस्ताव के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने मंत्रियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने विधायकों की सुरक्षा नहीं कर सकते व बिना पुलिस के एस्मा कानून तक नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए कामकाज लायक व्यवस्था कर (वर्केबल अरेंजमेंट) दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन की हड़ताल के समय एस्मा लगाया गया लेकिन पुलिस ने एस्मा लगाने में मदद नहीं की। उपराज्यपाल के पास कपिल मिश्रा से मिलने का समय है व भाजपा नेताओं से मिलने का समय है लेकिन परिवहन मंत्री से मिलने का समय नहीं है। ऐसे उपराज्यपाल पर लानत है।

हम अपनी और मंत्रियों की सुरक्षा कैसे करें? विधान सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में पंद्रह साल के शासन काल में बिजली की व्यवस्था दिल्ली से बेहतर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात की तुलना में शिक्षा व स्वास्य संबंधी व्यवस्था भी दिल्ली में ही बेहतर है।

गुजरात के काम काज की तुलना दिल्ली से करना चाहिए। इसलिए इनके पास एक ही चारा बचता है कि केजरीवाल को मरवा दो। केन्द्र सरकार हमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने देती है। मोहल्ला क्लीनिक नहीं बनाने देती है।

किसी पुलिस में हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री पर एफआईआर कर दे। ऐसा भाजपा के इशारे पर होता है। उन्होंने कहा कि चौथी बार सचिवालय में जब मिर्च फेंका गया तब गृह मंत्री ने सचिवालय की घटना के बाद मुझे फोन किया तो मैंने उनसे कहा कि आप निकम्मे हैं या उन लोगों से मिले हुए हैं। मेरा हाल उन्हीं से पूछ लीजिए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुराने शिक्षकों से ही सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो गई है व पुराने डाक्टरों से ही अस्पतालों की स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है।

अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन आती है तो यही पुलिस तुरंत बेहतर काम करने लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस वालों को कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर एक करोड़ की राशि दिए जाने के सरकार के निर्णय को रद्द करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस काफी मेहनत कर रही है इसलिए इस निर्णय के तहत दिल्ली के ग्यारह पुलिस वालों को एक करोड़ की राशि मिलेगी।

केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को नसीहत दी कि नरेन्द्र मोदी उनके काम नहीं आएंगे।

जब चाहो केजरीवाल के घर आकर कोई इलाज या एडमिशन करवा लो। आम आदमी पार्टी ही दिल्ली पुलिस के काम आएगी।

दखल

शादी का बीमा: समझदारी या फितूर

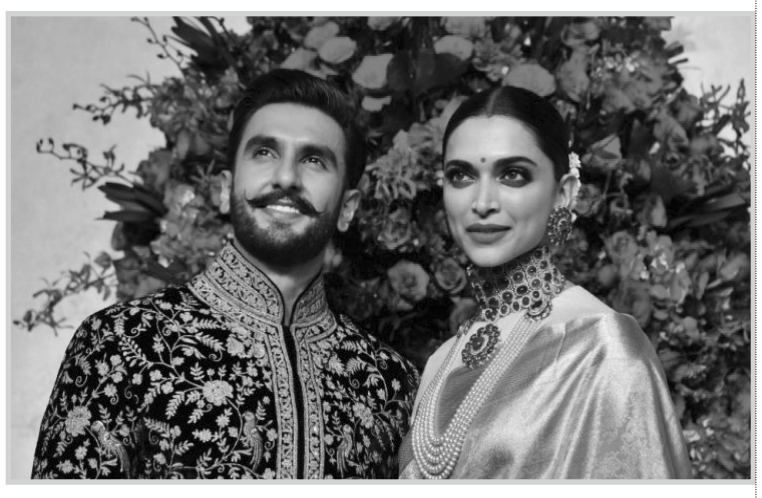

दीपिका और रणवीर सिंह की शादी का बीमा कई लोगों के लिए उत्सुकता पैदा करने वाला रहा। अभी देश में कई बीमा कंपनियां इस तरह का बीमा दे रही हैं। हालांकि, विवाह का बीमा अब तक सर्वस्वीकार्य नहीं है। एक-दो उदाहरणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि बीमा करा लेने भर से ही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मेट्रो शहरों में इस तरह का प्रचलन है, मगर छोटे शहरों में इस तरह की अवधारणा को बल नहीं मिला है।

पिछले सप्ताह यानी 13 और 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में बॉलीवुड के दो सितारों दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की हुई शादी कई वजहों से चर्चा में रही जिसकी एक बड़ी वजह इस शादी का बीमा होना भी था। हाल के सालों में कई बॉलीवुड और गैर बॉलीवुड सितारों की शादियां हुई हैं, लेकिन उनमें से किसी ने अपनी शादी का बीमा नहीं कराया था जैसा कि दीपवीर यानी दीपिका और रणवीर सिंह ने अपनी शादी का कराया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने जिसने इन दोनों की शादी का बीमा किया उसने इसे अपने विज्ञापन की तरह भुनाया है जिससे बीमा बाजार के कई जानकारों को लगता है कि शायद प्रीमियम के नाम पर इन दोनों सितारों को कुछ देने की जगह बीमा कंपनी से ही अच्छी खासी फीस मिली होगी। बहरहाल मैरिज बीमा के विज्ञापन के लिए इस अप्रत्यक्ष ट्रिक को न भी इस्तेमाल किया जाता तो भी तथ्य यही है कि मैरिज बीमा पालिसी दिनोंदिन लोकप्रिय हो रही है विशेषकर मेट्रोज के मध्यवर्गीय लोगों के बीच। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में शादियां महज खुशियों की चंद घड़ियां भर नहीं होतीं बल्कि अच्छीखासी अर्थव्यवस्था होती हैं।

देश में हर साल औसतन 80 लाख से एक करोड़ शादियां होती हैं, जिनमें करोड़ों-अरबों रुपए खर्च होते हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में शादियां हर साल कितने लोगों को रोजगार देती होंगी। इस समय अर्थव्यवस्था में चाहे जिस तरह की मंदी आई दिखती हो लेकिन शादी का बाजार इस सबसे प्रभावित हुए बिना सालाना 25 से 30 प्रतिशत रफ्तार से प्रगति कर रहा है जैसा कि विभिन्न उद्योग संगठनों की तमाम अलग-अलग रिपोर्टें बताती हैं। वैसे तो हमारे यहां शादियों का खर्च तय नहीं है जिसकी जितनी हैसियत उतना खर्च करता है, लेकिन हाल के सालों में विभिन्न किस्म के खर्चों का जो एक साझा औसत निकाला गया है उसके हिसाब से देखें तो एक शादी में औसतन तीन लाख से पांच करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं।

भारत में शादियां अपने आप में एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था हैं यही कारण है कि भारत में हर साल होने वाली लाखों शादियों से तमाम कारोबारों को जीवन सांस मिलती है। मसलन सोने के कारोबार को ही ले लें। हमारे यहां हर साल 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने और हीरों के गहने सिर्फ शादियों के कारण ही बिकते हैं। यही नहीं इतने बड़े पैमाने पर होने वाली इन शादियों के चलते हर साल 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का टिकाऊ उपभोक्ता सामान विशेषकर फर्नीचर बिक जाता है जबकि 10 हजार करोड़ से ज्यादा के कपड़े बिक जाते हैं। पंडाल और डेकोरेशन इंडस्ट्री की भी जीवन सांसे हर साल बड़े पैमाने पर होने वाली शादियों से जुड़ी हैं। गोवा, जयपुर और उदयपुर जैसे खास शहरों की अच्छीखासी कमाई भी इन शादियों पर ही निर्भर होती है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार होने कारण शादी बाजार में देर सबेर बीमा कंपनियों की इंट्री तो होनी ही थी। शायद इसीलिए ओरियंटल इंश्योरेंस ने दीपिका-रणवीर की शादी का इंश्योरेंस बीमा न केवल भव्य तरीके से किया है बल्कि इसका खूब प्रचार भी किया है ताकि शादी बीमा क्या होता है इसे लोग अच्छी तरह से जान लें।

वैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस के मुंबई कार्यालय से जारी दीपिका और रणवीर के नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी में शादी की दोनों जगहों यानी भारत और भारत के बाहर का बीमा किया गया। यह बीमा पॉलिसी पूरे पांच दिनों यानी 12 से 16 नवंबर 2018 तक सक्रिय या लागू रही। इस बीमा के तहत शादीस्थल पर आग लगने, चोरी होने, विस्फोट होने या फिदायीन हमला होने, हवाई जहाज से कोई नुकसान होने, भूकंप आने, पानी से नुकसान होने, चोरी या डकैती, बाढ़, तूफान या टायफून आदि को कवर किया गया। इस तरह की इन दुर्घटनाओं के अलावा हड़ताल, दंगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान इसके दायरे में शामिल किया गया था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रचार के तौरपर इस बीमा पॉलिसी को कई दूसरे लोगों के पास भी भेजा। खासकर जिन घरों में निकट भविष्य में शादियां होनी हैं। वैसे लोगों को समझाने के लिए ओरिएंटल कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह पॉलिसी पूर्ण रूप से शादी का बीमा नहीं करती बल्कि विवाह में इस्तेमाल होने वाली ज्वैलरी पर ही लागू होती है। जहां तक मैरिज बीमा कौन-कौन सी कंपनियां करती हैं का सवाल है तो ओरिएंटल इंश्योरेंस के अलावा बजाज एलियांज, एचडीएफसी, एर्गो, यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी और आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसी बीमा कंपनियां शादी बीमा करती हैं। लेकिन सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। कई बार तो इनके ये क्राइटेरिया हर एक ग्राहक के साथ अलग-अलग हो जाते हैं। इसलिए इस संबंध में कोई अंतिम बात मान लेने की बजाय अगर मैरिज बीमा करवाना है, तो खुद सभी बीमा कंपनियों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करनी चाहिएए तब अंतिम और सच बात मालूम होती होती है कि आपको आपकी शादी के लिहाज से कैसा और कितना बीमा कवर मिल सकता है। जहां तक बीमित राशि का सवाल है वह भी अलग अलग बीमा कंपनियां अलग-अलग ऑफर देती हैं।

आमतौर पर प्रीमियम 0.50 से लेकर 3.25 प्रतिशत तक होता है। इस तरह 3500 से 14 हजार 275 रुपए में दो लाख से लेकर आठ लाख रुपए तक के जोखिम का बीमा कवर मिल जाता है। लेकिन बीमा कराने की सोचने वालों को यह बात याद रखनी ही चाहिए कि यह सुविधा सिर्फ विशेष परिस्थितियों और अधिकतम पांच दिनों की शादी की विभिन्न रस्मों के लिए ही होती है। वैसे 20 लाख से लेकर 70 लाख तक का बीमा होता है। लेकिन बीमित धनराशि आपके कहे गए के हिसाब से नहीं मान ली जाऐगी। दावे की विभिन्न राशियों के लिए दस्तावेजी सपोर्ट चाहिए होता है मसलन आपके गहनों को उतने का मान लेने के लिए जितने का आप बता रही हैंए बकायदा बिल और शुद्धता का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी अगर लाखों-करोड़ों की शादियों में कुछ हजार का बीमा कराकर तमाम किस्म की दहशत से थोड़ा बहुत मानसिक सुकून मिल जाए तो बीमा गलत नहीं है।

आजकल कई बार शादियों में चोरी या हंगामे की स्थिति से हम दो-चार होते रहते हैं। विवाह के दौरान दूल्हे को गोली मारने जैसी खबरें भी हमारे लिए अंजान नहीं हैं। अगर विवाह का बीमा कराया जाए, तो इस तरह की परिस्थितियों के बाद होने वाले मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। हालांकि, विवाह का बीमा अब तक सर्वस्वीकार्य नहीं है। एक-दो उदाहरणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि बीमा करा लेने भर से ही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कंपनियां कहती कुछ हैं और करती कुछ हैं। शादी का बीमा रणवीर और दीपिका की शादी के बाद ही सुनने में आया है। माना कि मेट्रो शहरों में इस तरह का प्रचलन है, मगर छोटे शहरों में इस तरह की अवधारणा को बल नहीं मिला है। इसलिए अभी दावे से यह नहीं कहा जा सकता कि बीमा कंपनियों के नए हथकंडे को आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा।

वीना सुखीजा
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

राज-विचार

स्कूल बैग बना रहा बच्चों को बीमार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के स्कूली बैग का बोझ कम करने के इरादे से नई गाइडलाइन तैयार की है। हर कक्षा के अनुसार स्कूल बैग का वजन तय किया गया है, पर जरूरत गाइडलाइन से ज्यादा उसके पालन की है, क्योंकि स्कूल मनमानी पर उतारू हैं।

प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. यशपाल कहा करते थे कि ज्ञान बस्ते के बोझ से नहीं शिक्षा देने के तरीके पर निर्भर करता है। उनकी अध्यक्षता में बनी समिति ने शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्त करने की सलाह दी थी, वो मानते थे बच्चे पढें तो खेल की तरह, वे किताबों से मिलें तो खिलौनों की तरह, देश-दुनिया का ज्ञान उन्हें लुका-छिपी से भी आसान लगे तथा परीक्षाएं उन्हें दोस्तों के गप्प-ठहाकों से भी सहज लगें। हैरान करने वाली बात है कि उनके नेतृत्व वाली समिति ने बच्चों के पाठ्यक्रम के बोझ में कम करने के लिए जो सिफारिशें की थी, उनको दो दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। देर से ही सही अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के स्कूली बस्तों का बोझ कम करने के इरादे से एक नई गाइडलाइन तैयार की है। कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चों के बैग के वजन कम कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों में नए नियमों को भेज दिया है।

नई गाइडलाइन के मुताबिक चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट, 2006 के अनुसार स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी कक्षा के छात्रों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन तैयार की है। कक्षा पहली और दूसरी के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 1.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बात कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवीं के छात्रों की करें तो स्कूल बैग का वजन दो से तीन किलो के बीच का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो छात्र कक्षा छठी और सातवीं में पढ़ते हैं उनके स्कूल बैग का वजन चार किलो निर्धारित किया गया है। वहीं कक्षा आठवीं और नवीं के छात्रों के लिए बैग का वजन 4.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। बात दसवीं की करें तो वजन पांच किलों होना चाहिए। सरकार का फैसला उम्दा है, क्योंकि सर्वे के अनुसार, बस्ते के बढ़ते बोझ के कारण बच्चों को नन्हीं उम्र में ही पीठ दर्द जैसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। इसका हड्डियों और शरीर के विकास पर भी विपरीत असर होने का अंदेशा जाहिर किया गया है।

स्कूल जाने वाले करीब 68 प्रतिशत बच्चे, जिसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो सात से 13 वर्ष के करीब 88 फीसदी बच्चे पीठ दर्द या उससे जुड़ी समस्या का शिकार हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण किताबों की बोझ, स्पोर्ट किट और उनके बैग हैं, जो बच्चों के वजन से करीब 40 से 45 फीसदी तक ज्यादा होता है। आज स्थिति यह है कि देश भर में लाखों बच्चों को भारी बस्ता ढोना पड़ रहा है। इनमें तमाम वे नामी-गिरामी स्कूल भी शामिल हैं जो पठन-पाठन के आधुनिक तरीके अपनाए हुए हैं। मोहल्ला ब्रांड अंग्रेजी स्कूलों के लिए तो भारी बस्ते शुभ लाभ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के कोमल मन-मस्तिष्क पर गैर-जरूरी दबाव बढ़ रहा है और उनका भारी बस्ता उन्हें उस उम्र में ही कुली बना रहा है, जो खेलने और कूदने की होती है।

शराब की बढ़ती खपत चिंताजनक

विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह रिपोर्ट चिंताजनक है कि भारत में पिछले एक दशक में शराब की खपत दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ है कि 2005 में प्रति व्यक्ति शराब की खपत 2.4 लीटर थी, जो 2016 में बढ़कर 5.7 लीटर हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर खपत पर रोक नहीं लगी तो 2025 तक इसमें और अधिक इजाफा होने की संभावना है। अगर खपत और बढ़ी तो फिर इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होंगे। इसलिए कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब पीने से 2016 में दुनिया में तकरीबन 30 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई जिनमें बड़ी संख्या भारत के लोगों की है। गौर करें तो शराब सेवन से होने वाली मौत का यह आंकड़ा एड्स, हिंसा और सड़क हादसों में होने वाले मौतों के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक शराब के सेवन से सैकड़ों किस्म की बीमारियां होती हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संभ्रांत व स्वस्थ समाज के विकसित होने की राह में खतरनाक बनती समस्या पर नियंत्रण लगाने की दिशा में ठोस पहल की वकालत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेडरोस ने कहा है कि शराब की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और वर्ष 2010 से 2025 के बीच इस वैश्विक खपत में 10 प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए ताकि एक स्वस्थ विश्व का निर्माण किया जा सके। उनकी मानें तो शराब पर अधिकाधिक टैक्स लगाकर और इससे संबंधित विज्ञापनों पर पाबंदी लगाकर लोगों के जीवन बचाने की दिशा में पहल की जा सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में पिछले एक दशक में शराब की खपत दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है। 2005 में प्रति व्यक्ति शराब की खपत 2.4 लीटर थी, जो 2016 में बढ़कर 5.7 लीटर हो गई है। शराब की इस तेजी से बढ़ती खपत स्वस्थ समाज के लिए घातक है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को शराब के प्रति एक नीति बनानी होगी, ताकि युवा पीढ़ी को जहर पीने से बचाया जा सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट पर गौर करें तो मौजूदा समय में तकरीबन 23.7 करोड़ पुरुष और 4.6 करोड़ महिलाएं शराब से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें ज्यादतर संख्या भारत, यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोगों की है। आंकड़ों पर गौर करें तो आज की तारीख में भारत शराब की खपत के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत के बनिस्बत यूरोप में प्रति लीटर शराब की खपत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 10 लीटर है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जहां भारत में शराब की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वहीं यूरोप में 2010 के मुकाबले शराब की खपत में 10 फीसद तक की कमी आई है।

दरअसल, भारत में शराब की बढ़ती खपत का मुख्य कारण युवाओं का इसके प्रति बढ़ता आकर्षण और शराब उद्योग का तेजी से फलना-फूलना है। गौर करें तो देश में अल्कोहल निर्माता कंपनियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसा इसलिए कि शराब की मांग में तेजी आई है। विडंबना यह कि एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के बावजूद सरकारें शराब की खपत पर नियंत्रण को तैयार नहीं हैं। उसका मुख्य कारण भारी पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि अत्यधिक शराब के सेवन से सेहत और स्वास्थ्य पर खतरा मंडराना शुरु हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो शराब सेवन से लिवर सिरोसिस व कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों की मानें तो ज्यादा शराब पीने वाले लोगों में टीबी, एचआईवी व निमोनिया जैसी घातक बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में नियमित सेवन से दिमाग को भी नुकसान पहुंचने की संभावना प्रबल होती है।

विशेषज्ञों की मानें तो लंबे समय तक शराब के सेवन से पर्सनैलिटी डिसआनर जैसी समस्याएं उत्पन हो जाती हैं। ऐसे में अगर खपत पर लगाम नहीं लगी तो भारत जैसे विकासशील देश में रोगियों की तादाद में वृद्धि होगी व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह बिडंबना ही कहा जाएगा कि एक ओर जहां सरकार लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य योजना जैसी कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों के स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर शराब की खपत कम होने के बजाए बढ़ रही है, जबकि वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें संविधान के 47वें अनुच्छेद पर अमल कर शराब की खपत घटाएं, लेकिन देखा जा रहा है कि सरकारें इस दिशा में ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। हां, कुछ राज्यों ने शराबबंदी जैसे कठोर कदम उठाए हैं लेकिन देखा जा रहा है कि लोग चोरी-छिपे शराब पीने का तरीका निकाल लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अल्कोहल को नियंत्रित करने वाले कानून भारत के संविधान के 7वें कार्यक्रम में राज्य सूची में शामिल किया गया है। लिहाजा भारत में शराब से संबंधित कानूनों में कोई समानता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां भी इसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। देश में कई सरकारें ऐसी भी हैं जो शराब की खपत घटाने के बजाए उल्टे खपत बढ़ाने की नीतियों पर काम कर रही हैं।

दरअसल कुछ राज्यों में शराब की बिक्री से 20 प्रतिशत से भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। जबकि वे इस तथ्य से अच्छी तरह सुपरिचित हैं कि शराब लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है और इससे घर-परिवार तहस-नहस हो रहा है। दूसरी ओर शराब सेवन के कारण समाज में अपराध और बलात्कार जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे और समाज में शांति और समृद्धि का वातारण निर्मित करे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब समाज मानसिक रुप से स्वस्थ और नशामुक्त होगा। यह स्वीकारने में हर्ज नहीं कि कुछ दशक में केवल व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोहों में शराब सेवन का प्रचलन बढ़ा है और शराब सेवन को बुराई के तौर पर देखने की प्रवृत्ति कमजोर हुई है। अब भारतीय समाज में शराब के सेवन को आनंद और खुशी से जोड़ दिया गया है। उसका कुपरिणाम यह है कि युवा वर्ग शराब सेवन की ओर तेजी से आकर्षित हुआ है। सामाजिक संगठनों की मानें तो युवाओं में शराब पीने के खतरों के प्रति जागरूकता का नितांत अभाव है। लिहाजा शराबखोरी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा है।

यहां यह भी ध्यान देना होगा कि शराब से सर्वाधिक नुकसान गरीबों का हो रहा है क्योंकि वे अपनी कमाई का तकरीबन 45 फीसद हिस्सा शराब पर खर्च कर देते हैं। दिन भर काम करते हैं और उससे होने वाले आय को शराब पर उड़ा देते हैं। इससे न केवल उनका आर्थिक नुकसान होता है बल्कि स्वास्थ्य और सेहत भी बिगड़ता है। गौर करें तो ऐसे परिवारों की महिलाओं को सबसे अधिक त्रासदी भोगनी पड़ती है। जब भी वे शराब सेवन का विरोध करती हैं उन्हें किस्म-किस्म की प्रताड़ना सहनी पड़ती है। इससे विवाह विच्छेद जैसी स्थिति उत्पन होती है और परिवार का ताना-बान बिखरने लगता है। ध्यान देना होगा कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है, वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है। संगठित गिरोहों के जरिए शराब बिक्री का धंधा फलता-फूलता है। चूंकि इन संगठित गिरोहों को राजनीतिक और स्थानीय प्रशासन का संरक्षण हासिल होता है लिहाजा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं होती है। उसका परिणाम यह होता है कि इन राज्यों में देशी और जहरीली शराब की बिक्री रुकती नहीं है।

देखा भी जाता है कि ऐसे राज्यों में अक्सर जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं। उचित होगा कि सरकारें ऐसे जहरीली शराब की भट्ठियों, शराब माफियाओं और उन्हें संरक्षण देने वाले स्थानीय प्रशासन के नेक्सस को तोड़े और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। धीरे-धीरे ही सही शराब उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को उत्पादन क्षमता घटाने के लिए कानून बनाएं। हालांकि, यह काम एक-दो दिन में नहीं होगा।

अभिजीत मोहन
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

स्कूली बच्चों के बैग का वजन कम करने की कवायद कई दिनों से चल रही थी। सरकार बच्चों के कोमल शरीर को बचाए रखने की मंशा रखती है और उसे पूरा भी करेगी।

प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री

स्कूल बैग के वजन को लेकर सरकार को गाइडलाइन बनाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बच्चों की सेहत की चिंता स्कूलों को भी करनी चाहिए। सिर्फ कमाई की नहीं सोचनी चाहिए।

योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता

सत्यार्थ

लोकहित का संकल्प

कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक रूढ़िग्रस्त ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का विवाह मात्र नौ वर्ष की उम्र में कर दिया गया। मात्र 14 वर्ष की आयु में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के 10 दिन बाद शिशु की मौत हो गई। कारण, मां की कम उम्र के कारण शिशु को पर्याप्त पोषण व समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई। मां, जो स्वयं एक किशोरी थी, वह यह आघात सहन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वह जब भी अपने आसपास ऐसी कोई घटना देखती, तो वह उस पर गहरा दुख महसूस करती कि वह कुछ नहीं कर पा रही है। फिर, एक दिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह स्वयं डॉक्टर बनेगी और नन्हें शिशुओं और दूसरे रोगियों को अकाल मौतों से बचाने का प्रयास करेगी। उसने इस फैसले के बारे में पति को बता दिया। पत्नी की इच्छा को सम्मान देते हुए उन्होंने भी इस कार्य में पूरा सहयोग देने का फैसला किया। पति के सहयोग और अपनी उत्कृट इच्छा के बल पर वह सारी बाधाएं पार करती गई और आखिरकार मेडिसिन की पढ़ाई करने अमेरिका चली गई। वहां प्रतिकूल मौसम के कारण पहले से ही अस्वस्थ चल रही इस युवती को क्षयरोग हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी व मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही स्वदेश लौटी। लौटने पर देश में उनका भव्य स्वागत किया गया। आते ही उन्होंने चिकित्सक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि, वे ज्यादा दिन तो जीवित नहीं रहीं। एक वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वे युवती और कोई नहीं, हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थीं। लोकहित में लिया गया उनका दृढ़ संकल्प व अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे पूरा करने का साहस आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है।

आशा गुप्ता

सार समाचार

ट्रंप की चेतावनी, ब्रेग्जिट से ब्रिटेन-अमेरिका के बीच व्यापार हो सकता है प्रभावित

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चेतावनी दी कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने से लंदन और वाशिंगटन के बीच व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, ''ऐसा लगता है कि यह यूरोपीय संघ के लिए एक अच्छा सौदा है।'' उन्होंने आगे कहा, ''लेकिन हमें गंभीरता से यह देखना होगा कि ब्रिटेन को व्यापार करने की इजाजत है या नहीं।'' उन्होंने कहा, ''फिलहाल इस समझौते को देखा जाए तो हो सकता है कि वह हमारे साथ व्यापार नहीं कर सकें और यह कोई अच्छी बात नहीं होगी।'' ट्रंप ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा चाहते हैं। समझौते का सबसे अधिक नकारात्मक पक्ष यह होगा।''उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री टेरेसा मे इस बारे में कुछ कर सकेंगी।

मेक्सिको ने अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे शणार्थियों को किया गिरफ्तार

तिजुआना (मेक्सिको)। मेक्सिको ने तिजुआना में तारबंदी को पार कर अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे कई शणार्थियों को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। उन पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां भी छोड़ीं गईं थीं। करीब 5000 शरणार्थी अमेरिका में दाखिल होने के लिए तिजुआना में एकत्रित हुए, जिनमें अधिकतर होंडुरास के हैं। इनमें से पुरुष, महिला और बच्चों सहित करीब 5000 लोगों ने रविवार को तारबंदी पर चढ़ सीमा पार करने की कोशिश की थी। गश्ती दल के प्रमुख एजेंट रॉडनी स्कॉट ने 'सीएनएन' को बताया कि कई शरणार्थियों ने सीमा पार करने की कोशिश की, जिनमें से 42 को गिरफ्तार किया गया। मेक्सिको के राष्ट्रीय आव्रजन संस्थान के आयुक्त जेरार्डो गार्सिया ने अपनी देश की ओर 98 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने काफिले में लोगों को गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करने के लिए उकसाया था। कल कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में 'अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) कार्यालय' ने बताया था कि घटना के बाद सैन सिदरो सीमा चौकी को उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। 'सैन सिदरो सीमा चौकी' अमेरिका और मेक्सिको सीमा पर स्थित सबसे व्यस्त क्रॉसिंग है।

कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर उड़ान नहीं भर रहे अमेरिकी बमवर्षक विमान

विशिंगटन। अमेरिका के एक जनरल ने कहा है कि अमेरिकी बमवर्षक विमान तब से दक्षिण कोरिया के ऊपर से उड़ान नहीं भर रहे हैं जब से सियोल ने ऐसे अभियानों को रोकने का अनुरोध किया है। यूएस पैसिफिक एयर फोर्सेज के प्रमुख जनरल चार्ल्स ब्राउन ने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु संबंधी गतिविधियों का समाधान निकालने के लिये कूटनीतिक प्रयास जारी हैं और उनके लिए आगे की राह आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

26/11 पर पाकिस्तान को ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- भारत के साथ खड़ा है अमेरिका

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमले के निर्दोष पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सोमवार को कहा है, कि अमेरिका इस मामले में न्याय की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। और वह आतंकवादियों को कभी जीतने नहीं देगा। ट्रंप ने ट्वीट किया, ''मुंबई आतंकवादी हमले की 10 वीं बरसी पर अमेरिका इस मामले में न्याय पाने की भारत की जनता की इच्छा के साथ खड़ा है।''उन्होंने कहा, '' इस हमले में छह अमेरिकियों सहित 166 निर्दोष लोग मारे गए थे। हम आतंकवादियों को कभी जीतने या जीत के करीब नहीं आने देंगे।''

ट्रंप ने कहा, ''हम पाकिस्तान को एक साल में 1-3 अरब डालर देते हैं- (बिन लादेन)पाकिस्तान में रह रहा था, हम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, हम उन्हें एक साल में 1-3 अरब डालर दे रहे थे- जो अब हम उन्हें नहीं दे रहे हैं, मैंने इसे समाप्त कर दिया क्योंकि वे हमारे लिए कुछ नहीं करते, वे हमारे लिए कुछ भी नहीं करते।''

इन हमलों में अपने पति और 13 साल की बच्ची को गंवाने वाली महिला किआ चेर ने ट्वीट के लिए राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, ''यह दिन हमें घृणा पर प्यार की जीत की याद दिलाता रहे। यह ऐसी ताकत है जिसे गोली मार नहीं सकती। यह हमारी असली ताकत है। शुक्रिया।''

यहां पर भारतीय दूतावास में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के पीड़ितों की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अमेरिका के आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम के एक शीर्ष अधिकारी ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा तथा अन्य आतंकवादियों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की। विदेश मंत्रालय के आतंकवाद निरोधक समन्वयक नाथन सेल्स ने अपने संक्षिप्त बयान में कहा, ''हम सभी देशों खासतौर पर पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वे दोषियों को सजा दिलाने की अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सभी देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों और इसके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाएं।''

विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अंजाम देने वाले अथवा इसमें किसी प्रकार की सहायता करने वाले के बारे में कोई सुराग देने वाले व्यक्ति को 50 लाख डॉलर का इनाम देने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा, ''इसके साथ हम विश्व को यह याद दिलाते हैं कि हम 10 वर्ष पहले मारे गए लोगों को भूले नहीं हैं और हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि दोषियों को सजा नहीं मिल जाती।'' अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज सरना ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन हमलों में भारतीयों के अलावा 14 अन्य देशों के नागरिक भी मारे गए थे। उन्होंने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की आलोचना की। साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस हमले के दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने की पाकिस्तान से मांग करने को कहा। सरना ने विदेश मंत्रालय को ''रिवॉर्ड फॉर जस्टिस'' जैसे

कदम उठाने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस कार्यक्रम में मारे गए लोगों की याद में दो मिनट का मौन भी रखा गया। साथ ही इस अवसर पर परमार्थ संस्था 'वन लाइफ एलाइंस' की सह संस्थापक चेर द्वारा लिखे गए एक लेख के कुछ अंश भी पढ़ कर सुनाए गए। कार्यक्रम के अंत में एचबीओ का वृत्तचित्र 'टेरर इन मुंबई' भी दिखाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

26/11 के साजिशकर्ताओं को न्याय के दायरे में लाए पाकिस्तान- इज़राइल

लंदन (एजेंसी)।

तेल अवीव। इज़राइल ने मुम्बई के 26/11 हमले के 10 वर्ष पूरे होने पर पाकिस्तान से ''पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने'' की अपील की है। हमले में मारे गए 166 लोगों में छह इज़राइली नागरिक भी शामिल थे। सोमवार को यहां भारतीय मिशन में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान इज़राइल के विदेश मंत्रालय में 'दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया विभाग' के निदेशक माइकल रोनेन ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर पाकिस्तान सुनिश्चित करे कि इस घातक हमले के साजिशकर्ता और उनकी मदद करने

वाले बच ना पाएं। रोनेन ने कहा, ''पीड़ितों और उनके परिवार वालों को पूरा न्याय दिलाना बेहद महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने पाकिस्तान सरकार सहित सभी सरकारों से अपील की कि साजिशकर्ताओं और उनकी मदद करने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाए। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुम्बई को बम विस्फोटों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हमला 29 नवम्बर 2008 तक चला था। इसमें नौ आतंकवादी भी मारे गए थे और जिंदा पकड़े गए आतंकवादी कसाब को बाद में फांसी दी गई थी।

पाकिस्तानी महिला ने आईएसआईएस को साजो-सामान मुहैया कराने का अपराध कबूल किया

नई दिल्ली (एजेंसी)।

न्यूयॉर्क। पाकिस्तानी मूल की एक महिला ने एक स्कीम में भाग लेकर इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) आतंकी संगठन को साजो-सामान मुहैया कराने का अपराध कबूल कर लिया है। इस योजना में उसने पाकिस्तान, चीन और तुर्की में लोगों और फर्जी संस्थाओं को डेढ़ लाख डॉलर पहुंचाए जो आतंकवादी संगठन के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहायक अटार्नी जनरल जॉन सी डेमर्स ने कहा कि न्यूयॉर्क के ब्रेंटवुड में रहने वाली 27 साल की जूबिया शहनाज ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश जोआना सीबर्ट के सामने अपराध कबूल किया। पिछले साल दिसंबर में वाल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में जन्मी शहनाज अमेरिका की नैसर्गिक नागरिक हैं। वह एक परिवार आधारित आव्रजन प्रणाली का इस्तेमाल करके अमेरिका आई थी जिसके तहत उसे अमेरिकी वीजा मिल गया था।अदालत में दी गयी जानकारी के अनुसार मार्च 2017 से लेकर 31 जुलाई 2017 को सीरिया जाने की कोशिश करने वाले दिन तक शहनाज विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी वाली एक स्कीम में शामिल रही।

चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन के सबसे अमीर व्यक्ति और अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा चीन के सबसे मजबूत राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र पीपुल्स डेली ने यह जानकारी दी है। पार्टी पत्र में जैक मा के चीन के विकास में किये गये योगदान के लिये उनकी प्रशंसा की गई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या 8.9 करोड़ है जो उसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक बनाती है।

चीन के अखबार पीपुल्स डेली ने मा के कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य होने की खबर का खुलासा किया है। पीपुल्स डेली, कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक मुखपत्र है। कंपनी ने सोमवार को इस संबंध में एक आलेख लिखकर यह बात कही है। मा, ना तो पहले और संभवतः ना ही आखिरी ऐसे अमीर चीनी नागरिक हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने हैं।

इससे पहले रीयल एस्टेट कारोबारी शु जियायिन और वांडा समूह के संस्थापक वांग चियानलिन भी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जैक मा की सदस्यता के बारे में अब तक पता नहीं था। चीन के सबसे धनी व्यक्ति जैक मा अब तक यही कहते रहे हैं कि वह राजनीति से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। लेख में कहा गया है कि मा पार्टी के सदस्य हैं। चीन की वैश्विक व्यापार बुनियादी ढांचा क्षेत्र में की गई पहल 'बेल्ट एंड रोड' को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है।

मलेशिया में मंदिर बनाने को लेकर भड़की हिंसा, भारतीय श्रद्धालुओं पर हुआ हमला

सुबंग जया (मलेशिया) (एजेंसी)।

एक भारतीय मंदिर को कुआलालंपुर के बाहर प्रतिस्थापित करने को लेकर विवाद के बाद भड़के दंगों के सिलसिले में मंगलवार को 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया. मलेशिया पुलिस ने यह जानकारी दी. मध्य सेलंगोर प्रांत के सुबंग जया उपनगर में श्री महा मरिअम्मन मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे भारतीय श्रद्धालुओं पर घुसपैठियों के एक समूह ने सोमवार तड़के हमला किया और वाहनों को जला दिया.

हमले के बाद दंगा की घटना हुई. मंगलवार तड़के पुरुषों के एक अन्य समूह ने जवाबी हमला किया और मंदिर के नजदीक प्रॉपर्टी डेवलपर एमसीटी बेरहाद के कार्यालय में तोड़फोड़ की और कुछ वाहनों को जला दिया. मंदिर की जमीन का मालिकाना हक एमसीटी के यूनिट वन सिटी डेवलपमेंट एसडीएन. बीएचडी. के पास है और सौ साल पुराने मंदिर को पास के क्षेत्र में प्रतिस्थापित करने के लिए कानूनी लड़ाई चल रही है.

आतंकवादी घटनाओं के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए- यूएन

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र ने मुंबई आतंकवादी हमले की 10वीं बरसी पर कहा कि आतंकवादी हमलों में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को तथा हिंसा के किसी भी कृत्य को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टेफने डुजारिक से दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में सोमवार को कहा, ''सैद्धांतिक रूप से हम हमेशा यह मानते हैं कि जो भी हिंसा के लिए जिम्मेदार है...आतंकवाद के लिए कहीं भी हिंसा करने को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।''डुजारिक ने मुंबई हमले के 10 साल पूरा होने के मौके पर और इस हमले में शामिल लोगों के बारे में सुराग देने वाले को 50 लाख डॉलर का इनाम देने की अमेरिका के विदेश मंत्रालय की घोषणा के बारे में पीटीआई भाषा द्वारा पूछे जाने पर यह बात कही।

महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नान्डा एस्पिनोसा की प्रवक्ता मोनिका ग्रेले ने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अथवा लोग जो आतंकवादी हमलों में या हिंसा के किसी भी मामले में शामिल होते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।'' अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पिओ ने एक बयान में कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले की क्रूरता ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह पीड़ित परिवारों के लिए अपमान जैसा है कि घटना के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुंबई हमले की साजिश रचने वालों को उनकी संलिप्तता के लिए दोषी नहीं ठहराया गया।'' उन्होंने कहा, ''हम सभी देशों खासतौर पर पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वे हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा तथा उससे जुड़े संगठन और इसके लिए जिम्मेदार आतंकवादियों पर प्रतिबंध लागू करने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाएं।''

यूक्रेन की संसद ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने को मंजूरी दी

कीव (एजेंसी)।

यूक्रेन की संसद ने सोमवार को सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने को मंजूरी दे दी। उधर, रूस के सरकारी टेलीविजन चैनलों पर समुद्र में टकराव को लेकर मॉस्को के कीव के तीन जहाजों को जब्त कर लेने के बाद बंधक बनाए गए यूक्रेनी नाविकों की तस्वीरें प्रसारित की गईं। गहन चर्चा के बाद 276 सांसदों ने 30 दिन के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यह फैसला तब किया गया जब रूसी बलों ने रविवार को कीव के तीन जहाजों को जब्त कर लिया। रूस ने आरोप लगाया कि अजोव सागर में क्रीमिया के तट के पास जहाज अवैध तरीके से रूसी जल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे।

यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों का कहना है कि रूस ने अवैध तरीके से जलसंधि को अवरूद्ध किया और जहाज और नाविकों को बंधक बनाकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। मार्शल लॉ यूक्रेन के अधिकारियों को सैन्य अनुभव वाले नागरिकों को लामबंद करने, मीडिया का नियमन करने और जनसभाओं को सीमित करने की शक्ति देता है। पोरोशेंको समूचे देश में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध की वजह से इसे सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया।

मतदान से पहले पोरोशेंको ने मॉस्को पर 'नये चरण का आक्रामक बर्ताव' करने का आरोप लगाया। यूक्रेनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और बंधक बनाए गए नाविकों की कई तस्वीरें रूस के सरकारी चैनल रोसिया 24 पर प्रसारित की गईं, जिसमें मॉस्को की सुरक्षा सेवा के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एक समय में नाविकों में से एक को यह कहते सुना जा रहा है कि ''कर्च जलडमरूमध्य में यूक्रेन के सशस्त्र जहाजों की कार्रवाई उकसाने वाली प्रकृति की है।'' इस घटना से सैन्य गतिविधियां बढ़ने का डर पैदा हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने रूस को गैर कानूनी कार्रवाई के लिये चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी घटना का आकलन किया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ''जो कुछ भी हो रहा है हम उसे पसंद नहीं करते हैं और उम्मीद है कि सबकुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है कि यूरोप को भी अच्छा नहीं लग रहा है। वे भी इसपर काम कर रहे हैं। हम भी इसपर साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

यह टकराव रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में ताजा खतरनाक घटनाक्रम है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पहले ही संघर्ष को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और यूरोपीय राजधानियों ने सोमवार को कीव के प्रति समर्थन जताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री पावलो क्लिकिन ने कीव में संवाददाताओं से कहा, ''यह रूसी संघ की ओर से यूक्रेन के खिलाफ हमले का सुनियोजित कृत्य है।'' पोरोशेंको ने रूस पर लंबे समय से दोनों के बीच चल रहे संघर्ष को दूसरे स्तर पर ले जाने का आरोप लगाया।

सूरत। भाटिया टोल प्लाजा पर लोगों को नाश्ते और खाने पीने की चीजें अच्छी क्वालीटि में मिल सके इसके लिए अमूल द्वारा मिनी नाश्ते की स्टाल मंगलवार को नवसारी सांसद सी.आर.पाटिल के हाथों उद्घाटन कर शुरु की गई।

भाजपा के दो पूर्व विधायकों ने थामा कांग्रेस का हाथ

सूरत। जसदण उपचुनाव से पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। धंधुका के पूर्व विधायक लालजी मेर और मेहमदाबाद के पूर्व विधायक सुंदरसिंह चौहाण ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया।

लालजी मेर कोली समाज से आते हैं और उनके कांग्रेस में जाने से भाजपा को नुकसान की संभावना व्यक्त की जा रही है। लालजी मेर 2012 में अहमदाबाद जिले की धंधुका विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और 2017 तक विधायक रहे। दो दिन पहले ही लालजी मेर ने भाजपा में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राजकोट जिले की जसदण विधानसभा सीट पर 20 दिसंबर को उपचुनाव होना है और उससे पहले लालजी मेर का इस्तीफा भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा जा सकता है। जसदण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 35 प्रतिशत कोली हैं और 32 प्रतिशत कड़वा व लेउवा पाटीदार हैं। कांग्रेस ने जसदण उपचुनाव के लिए उ मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जबकि कुंवरजी बावलिया भाजपा के उ मीदवार हैं। कुंवरजी बावलिया भी कोली समाज से आते हैं और जसदण सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कुंवरजी बावलिया ने इसी वर्ष इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। बावलिया के इस्तीफे से जसदण सीट रिक्त हुई है।

दूसरी ओर खेडा जिले की मेहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक सुंदरसिंह चौहाण ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और कांग्रेस सांसद व गुजरात प्रभारी राजीव सातव की मौजूदगी में सुंदरसिंह चौहाण ने आज हाथ थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही सुंदरसिंह चौहाण ने कहा कि अब मैं भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ गया हूं। चौहाण समाज से अनुरोध है कि वह भी कांग्रेस का साथ दें। भाजपा अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही।

पांडेसरा में दारू, जुआ, गांजा का फलता फूलता गोरख धंधा, प्रशासन लाचार?

सूरत। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पांडेसरा इलाके की हर गली मोहल्ले में भरी संख्या में जगह-जगह जुआ ,गांजा दारू का धंधा चल रहा हैं। इस पर कई लोगों द्वारा लिखित फरियाद करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नही की जाती। पांडेसरा के लोगों का कहना है कि उचे पदों पर बैंठे अधिकारियों की मिली भगत से यह गोरख धंधा फल-फुल रहा हैं। इस क्षेत्र के कापोरर्टर, विधायक इस बात पर ध्यान नही दे रहे हैं। सूरत महानगर पालिका की खुल्ली जगहों पर दारू, गांजे का धंधा कनरे वाले ने कब्जा कर रखा है, जिससे यहां के लोगों को दारू और गांजा पीने के बूरी लत लगी हुआ है। दारू, गांजे का धंधा मणिनगर ,नाग सेन नगर , नेम नगर , के सामने प्रभु नगर गाँधी कुटीर रोड के पास हरिओम नगर के पीछे खुल्ली जगहों पर हो रहे हैं, इस मुद्दों पर न तो महानगर पालिका और न तो प्रशसन ध्यान दे रहा हैं। क्या पांडेसरा पुलिस इतनी लाचार है की दारु और गांजे के धंधा करने वाले माफियाओं के सामने अपनी आंख चुरा कर निकल जाती है और उनके धंधों को बंद कराने के लिए कुछ नहीं करती। पिछले दिनों सूरत शहर में दारू बंदी कराने के लिए शहर के पत्रकारों द्वारा गांधी प्रतिमा चौक बाजार में धरना भी दिया गया लेकिन उन्हे मिला क्या सिरफ आश्वासन। देखना होगा की क्रांति समय के संपादक द्वारा बेबाकी से लीखी गई इस खबर को पढने के बाद अधिकारियों का जमीर जागता है भी या नहीं। पांडेसरा के लोगों का कहना है कि ये असामाजिक तत्व अब मुहल्ले की बहु-बेटियों की तरफ की गल्त हरकते करने लगे है। क्या इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी ?

शिक्षा व्यवस्था हो ऐसी, जिसमें हो बिना बोझ के पढ़ाई: मुख्यमंत्री

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बिना बोझ के पढ़ाई की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य में ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के तहत ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मंशा जताई है जिसमें वर्चुअल कक्षाओं के जरिए आगामी दिनों में बच्चों को सिर्फ एक लैपटॉप में ही सभी पुस्तकों-विषयों का ज्ञान सुलभ हो जाए। मंगलवार को पंचमहाल जिले के मध्य प्रदेश की सीमा से सटे जांबुघोड़ा में राज्यव्यापी शाला स्वास्थ्य-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट का राज्यव्यापी क्रियान्वयन कर स्कूलों में प्रोजेक्टर और लैपटॉप से शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ बाल-स्वस्थ गुजरात और तंदुरुस्त गुजरात के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता कर बचपन से ही उनको असाध्य रोगों से बचाने के लिए स्कूल स्वास्थ्य-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। रूपाणी ने बच्चों को ईश्वर का स्वरूप बताते हुए कहा कि राज्य में बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार ने यह राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इससे हजारों बच्चों को नवजीवन मिला है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत हृदय रोग, कैंसर, किडनी, बोन मैरो प्रत्यारोपण और कोकलियर इ प्लांट (मूक बधिर बच्चों के लिए) जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित बच्चों को सरकार द्वारा सुपर स्पेशियलिस्ट उपचार मुहैया कराया जा रहा है। रूपाणी ने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत गत वर्ष 1.55 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर 99 फीसदी उपलब्धि हासिल की गई है। जिसमें 19.91 लाख बच्चों को स्थल पर उपचार प्रदान किया गया जबकि 1.84 लाख बच्चों को संदर्भ सेवाओं का लाभ दिया गया है। 99210 बच्चों को नि:शुल्क चश्मा वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि 22932 बच्चों को हृदय रोग, 3508 बच्चों को किडनी रोग, 1843 बच्चों को कैंसर रोग, 626 क्ले ट लिप और पैलेट (कटे होंठ और तालू), 530 क्लब फुट (पैरों में टेढ़ापन) का उपचार प्रदान किया गया है। वहीं, 25 बच्चों को किडनी प्रत्यारोपण, 501 को कोकलियर इ प्लांट तथा 28 बच्चों के बोन मैरो प्रत्यारोपण का संपूर्ण उपचार राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क मुहैया कराया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि च्जहां नागरिक, वहां सुविधा के मंत्र के साथ राज्य सरकार समाज की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ काम कर रही है। उन्होंने जांबुघोड़ा कुमार शाला में चिकित्सक की वेशभूषा में सुसज्जित बाल डॉक्टरों के साथ संवाद कर बाल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचमहाल जिले में जनसुविधा और जनकल्याण के 472 लाख रुपए के छह विकास प्रकल्पों का लोकार्पण करने के साथ जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत माऔर मा वात्सल्य कार्ड के तहत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सफलतागाथा पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने मा योजना सहित आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरीत किया। उन्होंने राज्यव्यापी स्कूल स्वास्थ्य अभियान में जुड़कर तंदुरुस्त बाल-तंदुरुस्त समाज के निर्माण के लिए सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, गांवों, आदिवासियों और अंतिम व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली संवेदनशील सरकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश में पहली बार पेसा एक्ट को लागू कर 90 हजार आदिवासियों को जंगल का अधिकार प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाजी से लेकर उमरगाम तक के आदिवासी क्षेत्रों में 45 हजार करोड़ रुपए की वनबंधु कल्याण योजना के जरिए आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्कर्ष के कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सके इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा दाहोद में मेडिकल कॉलेज शुरू की गई है। रूपाणी ने महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण, स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व और 181 अभयम महिला हेल्पलाइन की सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। पंचमहाल जिले की विभिन्न संस्थाओं ने मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि के लिए 3.52 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया।

कृषि राज्य मंत्री जयद्रथसिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अहम कार्य कर रही है। आजादी के बाद वर्तमान सरकार के नेतृत्व में पंचमहाल जिले सहित जांबुघोड़ा तहसील का सर्वांगीण विकास हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉ. गौरव दहिया ने कहा कि स्कूल स्वास्थ्य-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष राज्य में स्कूल जाने और नहीं जाने वाले 1.59 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसमें 1.11 लाख से अधिक सरकारी एवं निजी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। इस कार्य के लिए राज्य में आरबीएसके की 992 टीमें कार्यरत की गई हैं।

सूरत में पहली बार सूफी और कथ्थक का फ्युजन सूफी टु सोल वकशोप का आयोजन

गिनीश रेकोर्डर मौना शाह मशरुवाला वर्कशोप कंडक्ट करेंगी

सूरत:- कोरस और जोय बकेट के संयुक्त उपक्रम में 'सूफी टु सोल वर्कशोप का आयोजन किया गया है। सूफी और कथ्थक फ्युजन सूफी ट सोल वर्कशोप में मात्र बहने ही भाग ले सकेंगी। प्रख्यात भारत नाट्यम और सूफी कथ्थक डान्सर और गिनीश बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में जिनका नाम है ऐसी मौना शाह मशरूवाला यह वर्कशोप कंडक्ट करेंगी।

सूफी को भक्तिके सबसे शुद्ध स्वरुप के रुप में पहचाना जाता है, जो ध्यान-योग के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस सूफी और भारतीय परंपरा के प्राचीन कथ्थक नृत्य का संयोग करके नृत्यांगना मौना शाह मशरूवाला ने एक नया और अद्भूतभूत फ्युजन तैयार किया है। जो सूरत की नृत्यप्रिय पांच वर्ष या उससे अधिक बहने सिख सके इस आशय से सूरत में वीआईपी रोड अफीरा बिजने हब में टोप फ्लोर के कोर के बैंकवेट होल में आगामी 3 दिसम्बर से 14दिसम्बर दौरान आयोजित होगा।

जोय बकेट के पायलने कहा कि 'सूफी शैली के फ्युजन नृत्य से आप ईश्वर को सीधे आत्मा के साथ जोड सकते हो, उस शद्ध भावना का अनुभव करने के लिए वर्कशोप में शामिल होना आवश्यक है। बहनों के लिए घर बैठे गंगा समान इस वर्कशोप के अंत में ग्रान्ड फिनाले होगा। जिसमें स्वयं मौना शाह मशरूवाला परफोर्म करेंगी। साथ ही अन्य लेडी सूफी सिंगर भी परफोर्म करेंगी। साथ ही वर्कशोप में जिन बहनों ने भाग लिया होगा वे बहने भी जो सीखी होंगी उसकी स्टेज पर से प्रस्तुति करेंगी।' सूफी शैली के डान्स फोर्म में रस लेने वाले लोगों को वर्कशोप में भाग लेने के लिए 9825148 561/9978977566 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है।

बड़ी संख्या में निवेशक CID क्राईम की ऑफिस में पहुंचे

अहमदाबाद। २६० करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी विनय शाह को गिरफ्तार करने के बाद निवेशको की आशा बठ गई है। निवेशको को उनके पैसे फिर से मिलने की आशा दिख रही है। जिसके चलते विनय शाह की गिरफ्तार के बाद एक दिन बाद बड़ी संख्या में विनय की स्कीम में पैसे लगाने वाले लोग सीआईडी क्राईम की ऑफिस में पहुंचे। विनय शाह को नेपाण से भारत लाने में अभी भी समय लग सकता है। आज १०० से भी अधिक निवेशको के निवेदन दर्ज किए गए। जांच और अधिक तेज बनने की संभावना दिख रही है। विनय शाह को अहमदाबाद लाने का इंतजार किया जा रहा है। कानुनी प्रक्रिया पुरी होने के बाद विनय शाह को नेपाण से लाया जाएगा। पैसा दुगुना-तिगुना करने का लालच देकर लोगों को २६० करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले अहमदाबाद के महाठग और ठग्स ऑफ गुजरात के रुप में चर्चा में आए शख्स विनय शाह को कल सोमवार के दिन नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। विनय शाह के पास से नेपाल पुलिस ने बड़ी मात्रा में डॉलर और यूरो बरामद किए थे। गुजरात सीआईडी और क्राइम टीम पिछले १५ दिनों से विनय शाह की तलाश कर रही थी। नेपाल पुलिस ने उसके साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया था जिसका नाम चंदा थापा बताया जा रहा है। हालांकि पैसा दोगुना-तिगुना करकने की स्कीम में साथ देने वाली विनय शाह की पत्नी भार्गवी शाह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गुजरात सीआईडी क्राइम के डीजी आशीष भाटिया ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पुरी करने के बाद विनय शाह को जल्द ही भारत लाया जाएगा। विनय शाह के पास से बरामद डॉलर और यूरो की कीमत ३४ लाख रुपये बताई जा रही है। सीआईडी क्राइम की एक टीम नेपाल के लिए रवाना होगी, ताकि विनय शाह को जल्द गुजरात लाया जा सके। पुलिस के मुताबिक विनय शाह और उसकी पत्नी ईमेल के जरिये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों ईमेल से घर बैठे ऑनलाइन विज्ञापन देकर निवेश की राशि को चंद महीनों में ही दो से तीन गुना करने का लालच देते थे। अहमदाबाद में विनय शाह और भार्गवी शाह के खिलाफ १० एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोनों आर्चर केयर डीजी एलएलएलपी, वर्ल्ड क्लेवर एक्स सॉल्यूशन नाम की कंपनी चलाते थे। ४५००, ९५००, २५००० रुपये के तीन स्कीमें कंपनी चलाती थी। इसी राशि को दो-तीन गुना करने का सांझा देकर पति-पत्नी लोगों को चूना लगाते थे। अहमदाबाद के वस्त्रापुर के थलतेज में प्रेसिडेन्ट प्लाजा में आर्चर केयर के कार्यालय को पुलिस ने सील कर दिया है। विनय शाह के पासे से लोपटोप, चार मोबाईल, छह एटीएम कार्ड और लाखो रुपये की फोरेन करन्सी मिलने के बाद इस मामले में भी जांच शुरू हो चुकी है। महाठग के रूप में चर्चा में आए विनय शाह की गिरफ्तार के बाद जिन लोगों ने अपने पैसे गवाये है उन लोगों को पैसे मिलने की आशा अब बढ़ गई है। गुजरात सीआईडी और क्राइम टीम पिछले १५ दिनों से टीप्स मिलने के बाद विनय शाह को गिरफ्त में लेने के लिए सक्रिय थी और आज आखिरकार आज इसे गिरफ्तार कर लिया गया।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)